हिरदेशाह बलिदान दिवस : 28 को भोपाल में आयोजन

क्रांतिवीर राजाओं और जनजातीय योद्धाओं के स्मरण का महापर्व है शौर्य यात्रा

- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी होंगे शामिल
- जम्बूरी मैदान में होगा भव्य आयोजन

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 25 अप्रैल. अखिल भारतीय लोधी, लोधा, लोध क्षत्रिय महासभा मप्र, नर्मदा टाईगर हिरदेशाह शोध संस्था तथा गोंड महासभा के तत्वावधान में 28 अप्रैल को नर्मदा टाइगर हिरदेशाह लोधी के बलिदान दिवस पर शौर्य यात्रा का आयोजन भोपाल के जम्बूरी मैदान पर आयोजित किया जा रहा है.

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव होंगे. प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम, मंत्री प्रहलाद पटेल कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे. कार्यक्रम में प्रदेशभर से लोधी समाज के दो लाख से अधिक लोग शामिल होंगे. राजधानी में ये समाज का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा, जिसका तैयारियां पूरी कर ली गई है.

यह जानकारी अखिल भारतीय लोधी, लोधा, लोध क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री जालम सिंह पटेल एवं पूर्व विधायक एवं युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रध्युम्न सिंह लोधी ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी. इस दौरान पटेल ने बताया कि यह आयोजन इतिहास की अनदेखी का शिकार उन क्रांतिवीर राजाओं और जनजातीय योद्धाओं के स्मरण का महापर्व है जिनके बलिदान से आजादी की नींव रखी जा सकी लेकिन उनके योगदान को इतिहासकारों के पूर्वाग्रहों ने गुमनाम बना दिया.

> जालम सिंह पटेल ने बताया कि ब्रिटिश हुकूमत ने देश में जमीनों को हड़पने के लिए तीन काले कानून बनाकर लागू किए थे. किसानों से उनकी आय का 6 से 30 गुना तक लगान वसूला जाने लगा था, जमीन को सिकमी पर देने के लिए भी रोक लगा दी गई थी इस कानून का उल्लंघन करने पर जमीन राजसात कर ली जाती थी, मृत्यु के बाद जमीन का नामांतरण बंद कर दिया गया था और जमीन राजसात की जल के लिए बढ़ा दिया गया इन कानूनों ने साधारण किसानों के साथ जमीदारों और राजाओं के लिए भी अपनी जमीन बचाना मुश्किल कर दिया था. हिरदेशाह लोधी ने इन कानूनों के खिलाफ दलित, पिछड़े और आदिवासी राजाओं को एकजुट कर क्रांति का शंखनाद किया.

> बुंदेला विद्रोह में गोंड राजा डेलन शाह ने बड़ी कुर्बानी दी. डेलन शाह को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 2000 रुपए इनाम घोषित किया था. डेलन शाह को पकड़ पाने में नाकाम अंग्रेजों की फौज ने उनके परिवार पर कहर बरपाया. 17 जनवरी 1858 को डेलन शाह के 16 परिवार सदस्यों और साथियों को एक साथ फांसी दे दी गई इसमें उनका पांच साल का पोता भी शामिल था. इसी दिन डेलन शाह के चार अन्य परिजनों को गोली मारी गई. डेलन शाह इस अन्याय से टूट गये और गिरफ्तार कर लिए गए.

मंत्रालय के गलियारे से

कन्हैया लोधी

पारिवारिक आयोजन में राजनीति के रंग

पिछले दिनों प्रदेश के एक कद्दावर मंत्री का पारिवारिक आयोजन हुआ. ये आयोजन पूरी तरह राजनीति के रंग में रंगा नजर आया. इस आयोजन में कमोबेश प्रदेश से जुड़े सभी बड़े नेता शुमार हुए, लेकिन चर्चा के केंद्र में तीन नेताओं की जुगलबंदी ज्यादा रही. इनमें दो केंद्रीय मंत्री और एक प्रदेश के मंत्री थे. ये तीनों ही नेता देर तक एक ही टेबिल पर बैठे रहे और एक-दूसरे की तारीफ करते रहे. अब वहां मौजूद लोग इस जुगलबंदी के मायने निकाल रहे हैं.

क्या मौका भुना पाएगी विपक्ष

प्रदेश में इस समय गेहूं की सरकारी खरीदी चल रही है. शुरूआती दौर में खरीदी केंद्रों में जमकर अव्यवस्था रही. इसे लेकर विपक्षी दल के नेताओं ने जमकर बयानबाजी की. बाद में व्यवस्थाएं सुधरी और फिर खरीदी केंद्रों में स्लॉट बुकिंग को बढ़ाकर ढाई गुना तक कर दिया गया, वहीं खरीदी के समय में भी इजाफा कर दिया गया. सवाल ये कि शुरू में बयानबाजी से सरकार को दबाव में लाने के बाद विपक्ष अब क्या इसकी क्रेडिट ले पाएगा और क्या मौके को भुना पाएगा? या फिर ये अवसर भी गुटबाजी की भेंट चढ़ जाएगा. ये देखना दिलचस्प होगा.

क्या फिर अनुशासन का पाठ पढ़ाएगी भाजपा

भाजपा एक बेहद अनुशासित राजनीतिक दल है. ये हम सब जानते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से बीजेपी से जुड़े नेताओं की बदजुबानी पार्टी को भारी पड़ रही है. पिछले साल एक कद्दावर मंत्री अपने बड़बोलेपन में ऐसे उलझे कि अब तक उबर नहीं पाए हैं, बाद में एक महिला मंत्री का बड़बोलापन चर्चा में रहा. पार्टी ने फिर उन्हें भी समझाइश देकर रवाना कर दिया. उसके बाद भी न तो मंत्रियों का बड़बोलापन रूका और न ही विधायकों का. सब को चेतावनी लगातार मिल रही है, लेकिन इस चेतावनी का दूसरे नेताओं पर असर दिख नहीं रहा है. पिछले दिनों एक विधायक ने अपने तेवर से पार्टी और सरकार को ही मुश्किल में डाल दिया. तो क्या एक बार फिर अनुशासन का पाठ पढ़ाने की जरुरत पड़ेगी.

जिम्मेदारी पड़ रही भारी

एक अपर मुख्य सचिव स्तर की अधिकारी को मिली जिम्मेदारी उन पर भारी पड़ रही है. उनके पास जो दायित्व है, वह पहले ही फुल टाइम जॉब है. इस बीच उन्हें एडिशनल चार्ज भी मंत्रालय से बाहर रे दिया गया है. ये चार्ज भी इतना महत्वपूर्ण है कि उसे भी इगनोर नहीं कर सकते. इसका असर उनके मिजाज पर दिख रहा है. बताया जा रहा है कि अब वे पहले से ज्यादा नाराज दिख रही हैं, इसका सीधा असर मातहतों पर पड़ रहा है. अब देखना है कि बदलाव में उन्हें कोई राहत मिलती है या नहीं.

एक नजर में

कुंए में 15 घंटे तक साथ रहे बछड़ा और तेंदुआ

पन्ना. जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहाँ एक सूखे कुंए में तेंदुआ और बछड़ा गिर गए, इस गहरे कुंए में दोनों तक़रीबन 15 घंटे तक साथ रहे. आश्चर्य की बात यह रही कि छोटे बछड़े को शिकारी तेंदुए ने किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया. बछड़ा और तेंदुआ के कुआ में गिरने की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने इन दोनों को सुरक्षित कुएं से बाहर निकाला. यह वाकया इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. संकट की घडी में दोनों के बीच बहुत ही आत्मीय और दोस्ताना रिश्ता कायम रहा, जबकि बछड़ा तेंदुए का पसंदीदा शिकार है.

पत्रकारों के सवालों पर इमरती देवी हुईं असहज

मुरैना. मध्यप्रदेश की पूर्व मंत्री इमरती देवी नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण बिल) को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता में उस समय असहज नजर आईं जब पत्रकारों ने उनसे विधेयक से जुड़े अहम सवाल पूछे. बिना तैयारी के पत्रकार वार्ता में पहुंची पूर्व मंत्री कई सवालों का संतोषजनक जबाव नहीं दे सकीं. पत्रकारों द्वारा लगातार पूछे गए सवालों से घिरने लगीं तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर ही निशाना साधना शुरू कर दिया. पूर्व मंत्री इमरती देवी ने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं के हित में कभी गंभीर प्रयास नहीं किए,जबकि वर्तमान सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध है.

दिव्यांगजनों के अधिकार हमारी प्राथमिकता

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा

नौकरियों में 4% आरक्षण दे रही सरकार

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 25 अप्रैल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि एक सच्चा विकसित समाज वही है, जहां दिव्यांगजन सिर्फ सहानुभूति के नहीं, वरन् देश के विकास में बराबरी, सम्मान, समान हक और अवसरों के अधिकारी हों.

दिव्यांगजनों के अधिकारों और अवसरों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि दिव्यांग, दिव्य शक्ति के दिव्य अंश हैं. देश की प्रगति के अभिन्न अंग भी हैं. हम अपनी पूरी संवेदनाओं के साथ दिव्यांगजनों के हितों के प्रति संवेदनशील हैं. मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्रदेश में विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र, शासकीय नौकरियों में 4 प्रतिशत आरक्षण, हर विभाग में समान अवसर के लिए पृथक प्रकोष्ठ (सेल), सार्वजनिक एवं शासकीय भवनों में सहज और सुगम आवागमन के लिए रैंप, वॉशरूम्स का इंतजाम, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जरूरत के मुताबिक सहायक उपकरणों का वितरण, सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए विवाह प्रोत्साहन जैसी अनेक योजनाएं प्रभावी रूप से लागू की जा रही हैं.

नज़र का नहीं, नजरिए का कमाल होता : सीएम

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नज़र का नहीं, नजरिए का कमाल होता है. जो अपनी कमी को भी ताकत बना लेता है, वही संसार में नया इतिहास रचता है. हमारे समाज में ऐसे अनेक दिव्यांगजन हुए हैं, जिन्होंने कवि, टीकाकार, लेखक, वैज्ञानिक, व्यवसायी, उद्यमी, शिक्षक, कलाकार और विचारक बनकर समाज में अग्रणी भूमिका निभाई है. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण के लिए कृत संकल्पित है. राज्य में विभिन्न संस्थानों के माध्यम से संकेत भाषा प्रशिक्षण, मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास और कौशल विकास के क्षेत्र में निरंतर काम हो रहा है.

श्रम न्यायालय के आदेश में कानून या क्षेत्राधिकार की कोई त्रुटि नहीं

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने नगर निगम जबलपुर की याचिका इस टिप्पणी के साथ निरस्त कर दी कि श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कानून या क्षेत्राधिकार संबंधी कोई त्रुटि नहीं है.

श्रम न्यायालय ने अपने आदेश में याचिकाकर्ता की उन आपत्तियों को निरस्त कर दिया था, जिनमें निष्पादन कार्यवाही की स्वीकार्यता पर प्रश्न उठाते हुए यह तर्क दिया गया था कि यह समय-सीमा के कारण वर्जित है. दरअसल अनोवदक जबलपुर निवासी छोटेलाल खुरासिया की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार पांडे ने पक्ष रखा.

उन्होंने दलील दी कि इस याचिका के जरिए नगर निगम जबलपुर ने श्रम न्यायालय के 31 अक्टूबर 2025 के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके जरिए श्रम न्यायालय के अवार्ड के एग्जिक्यूशन की मेंटेनेबिलिटी के बारे में आपत्ति को निरस्त कर दिया गया था. नगर निगम ने एग्जिक्यूशन प्रोसिडिंग्स पर इस आधार पर आपत्ति जताई थी कि अवार्ड को एग्जिक्यूशन में लाने की समय-सीमा खत्म हो गई है और इसलिए एग्जिक्यूशन प्रोसिडिंग्स आगे नहीं बढ़ सकतीं.

नीट यूजी में सुरक्षा के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति

मकवाणा ने सभी पुलिस अधीक्षकों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

विशेष संवाददाता

भोपाल, 25 अप्रैल. नीट यूजी 2026 परीक्षा के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने पुलिस मुख्यालय में सभी जिला पुलिस अधीक्षकों के साथ उच्च स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक की.

बैठक में परीक्षा सुरक्षा, प्रश्नपत्रों के परिवहन, स्ट्रॉन्ग रूम निगरानी, साइबर मॉनिटरिंग और कानून-व्यवस्था से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तृत रणनीति तैयार की गई. 3 मई 2026 को आयोजित होने वाली इस परीक्षा को 'अत्यंत संवेदनशील' बताते हुए मकवाणा ने कहा कि यह लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ी है, इसलिए हर प्रक्रिया त्रुटिरहित और पारदर्शी होनी चाहिए. उन्होंने सभी परीक्षा केंद्रों, स्ट्रॉन्ग रूम और परीक्षा कक्षों का गहन भौतिक निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. साथ ही, परीक्षार्थियों की सुगम एंट्री के लिए पर्याप्त पुलिस बल और मेटल डिटेक्टर की व्यवस्था करने को कहा. प्रश्नपत्रों के सुरक्षित परिवहन और परीक्षा के बाद ओएमआर (ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन) शीट की वापसी तक कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं. बैंकों, डाकघरों और परीक्षा केंद्रों के बीच परिवहन के दौरान पुलिस एस्कॉर्ट, डैशकैम और निर्धारित रूट मॉनिटरिंग का उपयोग किया जाएगा.

> साइबर निगरानी को भी मजबूत किया गया है. साइबर कमांडो सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अफवाह, पेपर लीक या संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगे. किसी भी प्रकार की आपराधिक लापरवाही, प्रतिरूपण या संगठित नकल पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रदेश के 30 शहरों में 283 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें लगभग 1.18 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे.

बिजली कनेक्शन काटने से नाराज युवक ने की हत्या

सिंगरौली. बिजली कनेक्शन काटने की बात को लेकर उपजे विवाद में एक युवक ने 40 वर्षीय व्यक्ति की लाठी से पीट-पीटकर हत्या कर दी. चितरंगी पुलिस ने मामले में तेजी दिखाते हुए आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार, ग्राम सूदा निवासी भुनेश्वर उर्फ छंदू कोल (40) का शव 24 अप्रैल को संदिग्ध हालत में मिला था. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू की. जांच के दौरान संदेह के आधार पर पुलिस ने गांव के ही मुन्नालाल पनिका (28) को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक बार-बार उसका बिजली कनेक्शन काट देता था, जिससे वह नाराज था.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्व. केलकर की जयंती पर किया नमन

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के शिल्पकार स्व.यशवंतराव केलकर की जयंती पर पुण्य स्मरण कर उन्हें नमन किया है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्व. केलकर की व्यक्तित्व निर्माण और वैचारिक अधिष्ठान को मजबूत करने की अद्वितीय क्षमता से देश के असंख्य कार्यकर्ता संस्कारित हुए. उनका व्यक्तित्व हम सभी को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा.

भोपाल होकर दो विशेष ट्रेनों का संचालन

- यात्रियों की सुविधा के लिए प्रशासन ने निर्णय लिया

भोपाल, 25 अप्रैल. गर्मी के मौसम में यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए रेल प्रशासन ने भोपाल मंडल से गुजरने वाली दो विशेष ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है.

इससे इटारसी, भोपाल/रानी कमलापति स्टेशन और बीना के यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी.

पहली ट्रेन 01079/01080 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-गोरखपुर-छत्रपति शिवाजी टर्मिनस दैनिक विशेष गाड़ी है. यह 15 मई से 15 जुलाई 2026 (मुंबई से) और 17 मई से 17 जुलाई 2026 (गोरखपुर से) तक प्रतिदिन चलेगी, कुल 62 फेरे लगाए जाएंगे. इसमें 22 कोच होंगे, जिनमें एसी द्वितीय, एसी तृतीय, स्लीपर, सामान्य और एसएलआर शामिल हैं. दूसरी ट्रेन 01415/01416 पुणे-गोरखपुर-हडपसर दैनिक विशेष गाड़ी है. यह 15 मई से 15 जुलाई 2026 (पुणे से) और 16 मई से 16 जुलाई 2026 (गोरखपुर से) तक प्रतिदिन चलेगी, कुल 62 फेरे होंगे. इसमें 18 कोच रहेंगे.

> इन ट्रेनों के विस्तार से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच यात्रा के लिए अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध होंगे. यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले समय-सारणी और अन्य जानकारी एनटीईएस या रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट से अवश्य जांच लें.

नशीला पदार्थ सुंघाकर सोने के जेवरात लूटे

भिण्ड. भिण्ड बस स्टैंड पर मुरैना जिले के पोरसा निवासी शीला तोमर को नशीला पदार्थ सुंघाकर लूट की वारदात सामने आई है. गौरतलब है कि दो अज्ञात बदमाशों ने मायके (अतरसुमा) जाने के लिए ऑटो का किराया शेयर करने का झांसा दिया और रुमाल से नशीला पदार्थ सुंघाकर महिला को बेहोश कर दिया. इसके बाद आरोपी उन्हें ऑटो में ले गए और सोने के जेवर और 1500 रुपए नकद लूटकर दबोहा मोड़ पर उतारकर फरार हो गए. पीड़िता के बेटे की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है. घटना 13 अप्रैल की बताई जा रही है. पुलिस ने 25 अप्रैल यानी आज मुकदमा दर्ज किया है.

खजुराहो में तापमान 43.9 डिग्री

भोपाल, 25 अप्रैल. मध्य प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है. शनिवार को प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है, जिससे जनजीवन पर स्पष्ट असर दिखाई दे रहा है.

सुबह से ही तेज धूप लोगों को झुलसा रही है, जबकि दोपहर में हालात और अधिक गंभीर हो जाते हैं. अधिकांश जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ है.

छतरपुर जिला इस समय सबसे अधिक गर्म बना हुआ है. यहां के खजुराहो में तापमान 43.9 डिग्री और नौगांव में 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा रतलाम में 43.2 डिग्री, सतना और टीकमगढ़ में 42.8 डिग्री, दमोह में 42.6 डिग्री, जबकि मंडला और रीवा में 42.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया. धार, सीधी और रायसेन में भी तापमान 42 डिग्री से ऊपर रहा.

बड़े शहरों में भी गर्मी का असर कम नहीं है. ग्वालियर सबसे गर्म रहा, जहां तापमान 42.1 डिग्री दर्ज किया गया. भोपाल में 41.6 डिग्री, इंदौर में 41.2 डिग्री, जबलपुर में 42 डिग्री और उज्जैन में 41.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया.

> भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, धूप में निकलने से बचना, हल्के और सूती कपड़े पहनना जरूरी है. बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है. अगले चार दिनों तक प्रदेश में गर्मी का असर इसी तरह बना रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार महीने के अंत में कुछ राहत मिल सकती है. 27 और 28 अप्रैल को ग्वालियर, चंबल, जबलपुर और सागर संभाग के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है. यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण होगा, जिससे तापमान में आंशिक गिरावट आ सकती है.

राजनीति | 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को जनगणना और परिसीमन के बहाने रोका जा रहा : पटवारी

महिला आरक्षण पर आज कांग्रेस का विरोध मार्च

विशेष संवाददाता

भोपाल, 25 अप्रैल. मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार पर महिला आरक्षण कानून को जानबूझकर लागू न करने का आरोप लगाते हुए इसे राजनीतिक छल और वादाखिलाफी करार दिया है.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को जनगणना और परिसीमन के बहाने रोका जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को बिना किसी शर्त के लोकसभा में तत्काल लागू कराने के लिए सड़क से लेकर सदन तक

अपना आंदोलन तेज करेगी. इसी कड़ी में 26 अप्रैल को शाम 4 बजे भोपाल में एक बड़ा पैदल मार्च निकाला जाएगा. यह मार्च शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए रोशनपुरा चौराहे पर समाप्त होगा. कांग्रेस का कहना है कि इस मार्च के जरिए सरकार की कथित महिला विरोधी नीतियों को जनता के सामने लाया जाएगा.

पटवारी ने याद दिलाया कि स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण की शुरुआत राजीव गांधी के कार्यकाल में हुई थी, जिससे आज लाखों महिलाएं नेतृत्व की भूमिका में हैं. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि 2023 में पारित कानून अब तक लागू क्यों नहीं किया गया. उन्होंने नागरिकों से बड़ी संख्या में मार्च में शामिल होकर लोकतंत्र, संविधान और महिला अधिकारों की रक्षा के इस आंदोलन को मजबूत करने की अपील की.

सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक

भोपाल. विधानसभा के सोमवार को एक दिवसीय विशेष सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक बुलाई है. यह बैठक 27 अप्रैल को सुबह 9 बजे भोपाल स्थित उनके निवास पर आयोजित होगी. बैठक में महिला आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की जाएगी. कांग्रेस का आरोप है कि 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को लागू करने में संशोधनों का बहाना बनाकर जानबूझकर देरी की जा रही है. उमंग सिंघार ने कहा कि विशेष सत्र का उद्देश्य महिलाओं का सशक्तिकरण बताया जा रहा है, लेकिन सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकार असंवैधानिक उपायों के जरिए महिला आरक्षण को टालने की कोशिश कर रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस विधानसभा में ऐसे किसी भी प्रयास का कड़ा विरोध करेगी.

पेज एक का शेष

एक-दूसरे को महिला विरोधी साबित करने पर लगाएंगे दांव

इस चर्चा के दौरान राज्य सरकार मप्र में नगरीय निकाय के साथ ही त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने संबंधी प्रावधान का जिक्र कर स्वयं को महिलाओं की सबसे बड़ी शुभचिंतक के रूप में पेश करेगी. प्रदेश में पंचायतों में जहां वर्ष 2007 से महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है, वहीं नगरीय निकायों में वर्ष 2009 से 50 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान लागू किया गया है. उससे पहले 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान लागू था. जब ये बदलाव किया गया तो प्रदेश में भाजपा की ही सरकार थी. इस बीच पिछले दिनों लोकसभा में परिसीमन को लेकर बिल पेश किया गया, जिसमें लोकसभा की मौजूदा 543 क्षेत्रों को बढ़ाकर 850 किए जाने का प्रावधान किया गया था, इसी हिसाब से महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33 फीसदी आरक्षण दिया जाना था, लेकिन लोकसभा में लंबी चर्चा के बाद एनडीए की सरकार दो तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर सकी और बिल गिर गया. विपक्ष ने बिल का विरोध किया. लिहाजा मौके को भाजपा ने तुरंत लपका और देशभर में विपक्ष के खिलाफ मुहिम चलाकर उसे बिल गिरने के लिए जिम्मेदार ठहराया और महिला विरोधी करार दिया.

निंदा प्रस्ताव पेश नहीं करेगी सरकार: इस बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधानसभा के एक दिवसीय सत्र आहुत कराने की घोषणा कर दी, जिससे कि सदन में इस विषय पर चर्चा की जा सके.

संविधान के जानकारों के मुताबिक सदन में लोकसभा के बिल के पारित नहीं होने पर निंदा प्रस्ताव तो नहीं लाया जाएगा, ऐसा किया जाना विधि सम्मत नहीं होगा, लेकिन सदन में सरकार नारी सशक्तिकरण को लेकर संकल्प जरुर पेश कर सकती है, जिस पर चर्चा करायी जा सकती है और केंद्र सरकार से परिसीमन के साथ 33 फीसदी आरक्षण के प्रावधान को लागू करने का आग्रह किया जा सकता है.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा 3, इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स, रामगोपाल माहेश्वरी मार्ग, महाराणा प्रताप नगर, जोन-1, भोपाल से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि., इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स से मुद्रित. संपादक दिलीप झा*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-4939198, ईमेल-bhopalnav@gmail.com RNI Reg. No. 35046/56 डाक पंजीयन क्रमांक M.P/B.P.L/711/2012-14